



ALL INDIA FAIR PRICE SHOP DEALERS' FEDERATION

Regd. No. District East/Society/273-2011 of Govt. of NCT. of Delhi

Regd. Office : S-562, School Block, 'AKHAND HINDUSTHAN BHAWAN' Shakarpur, Delhi - 110 092, Mobile : 98110 12241/9871421221

Head Office : AC-164, Prafulla Kanan (East), Kestopur, Kolkata - 700 101, West Bengal

Phone : (033) 2591 3871 Mobile : 9875308556 / 98301 35530 / 9748777006, mail : gs@aifpsdf.org Website : www.aifpsdf.org WhatsApp : 9875308556 / 9830135530 Facebook : facebook.com@aifpsdf

Prof. Saugata Roy
Hon'ble M.P. Lok Sabha
Chief Advisor
Ph. : 2290 3272, 2422 0772
Mob. : 9830031220 / 9013180175

Shri Kacham Krishnamurthy
President
Mobile : 9849024567
8008018012

Shri Biswambhar Basu, B.Com, LLB
General Secretary
Ph. : (033) 2591-3871
Mobile : 98753-08556 / 98301-35530 / 97487-77000
WhatsApp : 98753-08556 / 98301-35530

Shri Dharani Dhar Borah
Treasurer
Mobile : 9678270358

Advisory Committee : Shri Pushparaj (Kaka) Deshmukh, Shri Kiranpal Singh Tyagi, Shri Kalicharan Gupta, Sardar Inderjit Singh

संदर्भसंख्या: AIFPSDF/335/25

दिनांक : 04.04.2025

बैठक का विवरण जिसमें एफपीएस डीलरों के भविष्य पर निर्णय लिया जाना था, 28-03-2025 को मुक्तधारा ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया गया था।

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कांचम कृष्णमूर्तिजी की अनुपस्थितिमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री ओंकार नाथ झा जी को बैठक की अध्यक्षता एवं संचालन की दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई।

बैठक में 13 (तेरह) राज्यों अर्थात असम, बिहार, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों और नेताओं ने भाग लिया और चर्चा में भाग लिया तथा भविष्य में एफपीएस डीलरों की बेहतरी के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में अपने विचार रखे।

"हम एफपीएस डीलरों के लिए न्याय चाहते हैं" यही टैगलाइन थी जिसके तहत आज की बैठक आयोजित की गई, जहां प्रतिष्ठित एफपीएस नेताओं ने वर्तमान परिदृश्य में देश भर के एफपीएस डीलरों के भविष्य के बारे में प्रभावशाली चर्चाओं में भाग लिया।

आरंभ में उन डीलरों के लिए एक मिनट का मौन रखा गया, जिनकी मृत्यु पिछली बैठक (वर्चुअल) से लेकर इस बैठक तक हो चुकी है।

राष्ट्रीय महासचिव श्री बिश्वम्भर बासु ने बैठक में भाग लेने के लिए कष्ट उठाने वाले तथा देश के विभिन्न भागों से दिल्ली तक आने वाले सभी लोगों का स्वागत किया।

बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कितीन ग्रह शनि, राहु और केतु ने हमारे व्यापार को घेर रखा है और इसे परिभाषित भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा किबेरोजगारों को रोजगार के बजाय मुफ्त राशन देने के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी शनिहै, डीबीटी के लिए बैंक खाते को लिंक करना राहु है और अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की पात्रता के बारे में आयकर विभाग द्वारा किया गया आकलन केतु है।

राष्ट्रीय महासचिव ने उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध किया किवे प्रत्येक जिले से 1 (एक) वास्तविक लाभार्थीके राशन कार्ड, आधार कार्डऔर मोबाइल नंबर की फोटोकॉपी एकत्र करें और इसे अपने राज्यों के नेताओं को भेजें, जो बदले में इसे फेडरेशन के कोलकाता स्थित मुख्यालय को भेजेंगे ताकियदिसरकार डीबीटी को लागू करने का निर्णय लेती है तो विशेष अनुमतियाचिका दायर की जा सके।

बोलने वाले नेता एकजुट थे और निम्नलिखित के संबंध में एक स्वर में बोले:-

- 1) डीबीटी- इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए।
- 2) कोरोना- डीलरों ने महामारी के दौरान लाभार्थियों की सेवा करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और किसी को भी भूख से मरने नहीं दिया।
- 3) मार्जिन- मार्जिन में वृद्धिआवश्यक है लेकिन सबसे पहले पीडीएस को सरकार की बुरी नजर से बचाना होगा।
- 4) उचित मूल्य की दुकान डीलरों के लिए वेतन प्रणाली लागू करने अथवा प्रतिदुकान प्रतिमाह 50,000 रुपये की न्यूनतम आय गारंटी सुनिश्चित करना।

आरंभ में ही देश भर से आए नेताओं से अनुरोध किया गया किवे अपने राज्यों की समस्याओं पर चर्चाया भाषणन करें, बल्किविशेष रूप से दो बिंदुओं (1) डीबीटी और (2) आंदोलन के तरीके पर बोलें।

बैठक के दौरान 2 (दो) पुस्तिकाएँ वितरित की गईं, जिनका शीर्षक था (1) खाद्य सचिवों का सम्मेलन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडी, एनएफएसए, बीपी प्रभाग) 28 फरवरी, 2025 (2) विभिन्न मुद्दों पर टीपीडीएस नियंत्रण आदेश में प्रस्तावित सुधार, जिसकी लागत मूल्य 300 रुपये मात्र है। (3) हमारे मुख्य सलाहकार, माननीय प्रोफेसर सौगत रॉय, सांसद (लोकसभा) द्वारा लोकसभा में उठाए गए प्रश्नों की प्रतिऔर माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और



ALL INDIA FAIR PRICE SHOP DEALERS' FEDERATION

Regd. No. District East/Society/273-2011 of Govt. of NCT. of Delhi

Regd. Office : S-562, School Block, 'AKHAND HINDUSTHAN BHAWAN' Shakarpur, Delhi - 110 092, Mobile : 98110 12241/9871421221

Head Office : AC-164, Prafulla Kanan (East), Kestopur, Kolkata - 700 101, West Bengal

Phone : (033) 2591 3871 Mobile : 9875308556 / 98301 35530 / 9748777006, mail : gs@aifpsdf.org Website : www.aifpsdf.org WhatsApp : 9875308556 / 9830135530 Facebook : facebook.com@aifpsdf

Prof. Saugata Roy
Hon'ble M.P. Lok Sabha
Chief Advisor
Ph.: 2290 3272, 2422 0772
Mob.: 9830031220 / 9013180175

Shri Kacham Krishnamurthy
President
Mobile : 9849024567
8008018012

Shri Biswambhar Basu, B.Com, LLB
General Secretary
Ph. : (033) 2591-3871
Mobile : 98753-08556 / 98301-35530 / 97487-77000
WhatsApp : 98753-08556 / 98301-35530

Shri Dharani Dhar Borah
Treasurer
Mobile : 9678270358

Advisory Committee : Shri Pushparaj (Kaka) Deshmukh, Shri Kiranpal Singh Tyagi, Shri Kalicharan Gupta, Sardar Inderjit Singh

सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार की राज्य मंत्री श्रीमती निमूबेन जयंतीभाई बंभानिया जी द्वारा दिए गए उत्तर भी पुस्तिकाओं के साथ वितरित किए गए। हम प्रोफेसर सौगत राँय के प्रयासों की सराहना करते हैं।

राष्ट्रीय महासचिव श्री बिश्वम्भर बासु ने सदन को अवगत कराया किमाननीय सांसद, लोकसभा एवं हमारे मुख्य सलाहकार प्रो. सौगत राँय ने आज (28.03.2025) अपनी नियुक्तिहेतु 3 (तीन) अनुरोध पत्र भेजे हैं:-

(क) भारत की महामहिम राष्ट्रपति,

(ख) माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री,

(ग) प्रो. राँय ने हमारे राष्ट्रीय महासचिव को आश्वासन दिया कि वे एक-दो दिन में माननीय गृह मंत्री को याद दिलायेंगे ताकि हमारी आजीविका सुनिश्चित हो सके।

दिनांक 27.03.2025 को कृषिभवन, नई दिल्ली के हमारे दौरे के दौरान हमें पता चला कि "सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण - तकनीकी डाटा बेस को सुदृढ़बनाना" विषय की जांच के लिए खाद्य स्थायी समितिकी एक बैठक मैडम टीएमटी कनिमोझी, माननीय सांसद और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समितिकी अध्यक्ष की अध्यक्षता में संसद में उनके कक्ष में आयोजित की गई थी। जिसका विवरण भविष्य में आपके अवलोकन के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेजा जाएगा।

राष्ट्रीय कार्यसमितिकी बैठक समाप्त होने के बाद, 3 (तीन) सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन स्थित उनके कार्यालय में माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार से मुलाकात की और हमारे मार्जिन से संबंधित एक नियुक्तितय करने के लिए प्रोफेसर सौगत राँय का अनुरोध पत्र सौंपा और यह आश्वासन दिया गया कि बजट सत्र के बाद माननीय वित्त मंत्री कृपया हमारी शिकायतों के बारे में चर्चा करेंगी।

हमारे फेडरेशन के विभिन्न राज्यों के सभी नेताओं से अनुरोध किया गया था कि वे अपने स्थानीय सांसदों से संपर्क करके सदन में एफपीएस डीलरों से संबंधित प्रश्न उठाने का अनुरोध करें, लेकिन किसी ने भी फेडरेशन मुख्यालय को कोई प्रतिक्रिया नहीं भेजी। हालाँकि, राष्ट्रीय महासचिव ने सभी सांसदों (लोकसभा और राज्यसभा) से संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि वे आगामी मानसून सत्र में सदन में एफपीएस डीलरों की समस्याओं के बारे में उनके राजनीतिक जुड़ाव के बावजूद प्रश्न उठाएँ।

यह संकल्प लिया गया है कि हम अपनी लड़ाई तीन मोर्चों पर लड़ेंगे:

(1) दोनों सदनों में माननीय सांसदों द्वारा उठाए गए प्रश्न।

(2) अपने अधिकार के लिए सड़कों पर संघर्ष करके आंदोलन करना।

(3) कोर्टकेस।

न्यायालय में मामला दायर करने के लिए धनराशिकी आवश्यकता है और यह निर्णय लिया गया कि आरम्भ में प्रति एफपीएस 5/- रुपये की धनराशिकी प्रकृत की जाएगी, जिसे हमारे निम्नलिखित बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए।

ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन

एक्सिस बैंक लिमिटेड,

डनलप, कोलकाता शाखा

ए/सी नं: 913010012901331

आईएफएस कोड: UTIB0000236

एसबीटीआरएस: 236160



ALL INDIA FAIR PRICE SHOP DEALERS' FEDERATION

Regd. No. District East/Society/273-2011 of Govt. of NCT. of Delhi

Regd. Office : S-562, School Block, 'AKHAND HINDUSTHAN BHAWAN' Shakarpur, Delhi - 110 092, Mobile : 98110 12241/9871421221

Head Office : AC-164, Prafulla Kanan (East), Kestopur, Kolkata - 700 101, West Bengal

Phone : (033) 2591 3871 Mobile : 9875308556 / 98301 35530 / 9748777006, mail : gs@aifpsdf.org Website : www.aifpsdf.org WhatsApp : 9875308556 / 9830135530 Facebook : facebook.com@aifpsdf

Prof. Saugata Roy
Hon'ble M.P. Lok Sabha
Chief Advisor
Ph. : 2290 3272, 2422 0772
Mob. : 9830031220 / 9013180175

Shri Kacham Krishnamurthy
President
Mobile : 9849024567
8008018012

Shri Biswambhar Basu, B.Com, LLB
General Secretary
Ph. : (033) 2591-3871
Mobile : 98753-08556 / 98301-35530 / 97487-77000
WhatsApp : 98753-08556 / 98301-35530

Shri Dharani Dhar Borah
Treasurer
Mobile : 9678270358

Advisory Committee : Shri Pushparaj (Kaka) Deshmukh, Shri Kiranpal Singh Tyagi, Shri Kalicharan Gupta, Sardar Inderjit Singh

निम्नलिखित आंदोलनात्मक कार्यक्रम तय किया गया:-

(ए) अप्रैल, 2025 के महीने के दौरान, एफपीएस डीलर एक हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे (पोस्ट कार्ड पर प्रोफार्माजल्ड ही सभी को भेजा जाएगा, जिसे सीधे माननीय प्रधान मंत्री को उनके कार्यालय 152, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011 में भेजा जाएगा)।

(बी) मई 2025 के दौरान सभी ब्लॉकों, उप-क्षेत्रों, थानों, उप-मंडलों और उप-नियंत्रणों में संगठनात्मक तैयारी बैठकें।

(सी) दिनांक 09.06.2025 को- जिला स्तरीय आंदोलन कार्यक्रम।

(घ) 30.06.2025- राज्य स्तरीय रैली एवं आंदोलनात्मक कार्यक्रम।

(ई) 31.07.2025- संसद मार्चके बाद जंतरमंतर, नई दिल्ली में आंदोलन कार्यक्रम जिसमें माननीय प्रधान मंत्री, माननीय वित्त मंत्री और माननीय केंद्रीय खाद्य मंत्री के आवासों का घेराव शामिल होगा।

विभिन्न स्तरों पर प्रस्तुत किए जाने वाले जापन हमारे प्रधान कार्यालय, कोलकाता से सभी को भेजे जाएंगे, जिसमें राज्य के नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव के परामर्शसे अपनी राज्य स्तरीय समस्याओं को जोड़ने की सलाह दी गई है।

अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के लिए हमारे संगठन के विभिन्न स्तरों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जानी चाहिए।

यदि एकीकृत वजन तराजू का उपयोग एनएफएसए में निर्धारित अतिरिक्त मार्जिन के बिना किया जाना है:-

- (1) ई-पीओएस उपकरणों की शुरुआत के बाद से 17 रुपये प्रतिक्विंटल और अप्रैल 2022 से 21 रुपये प्रतिक्विंटल।
- (2) अभी तक वितरण इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू के माध्यम से किया जा रहा है, जिसे संबंधित राज्य सरकारों के माप विज्ञान विभाग द्वारा प्रमाणित किया गया है। इन्हें समाप्त या वापस नहीं लिया गया है। अतिरिक्त मार्जिन की अनुमति दिए बिना, सरकार ने एकीकृत तौल तराजू के साथ राशन वितरित करने का आदेश दिया, माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई है। अन्य सभी राज्य इकाइयाँ हमारी पश्चिम बंगाल इकाई द्वारा की गई कार्रवाई का अनुसरण कर सकती हैं।
- (3) नेटवर्क, सर्वर की समस्या होने पर ई-पीओएस का स्क्रीन शॉट सुरक्षित रखना चाहिए। नेटवर्क, सर्वर की समस्या होने पर इस अवधिमें मैनुअल वितरण किया जाना चाहिए।
- (4) यह सलाह दी गई है कि कुछ छाया क्षेत्रों की पहचान की जाए जहां सर्वर/नेटवर्कनियमित रूप से बंद रहता है।
- (5) सरकारी कर्मचारियों की मांग, सभी राज्यों में 60 वर्षया उससे अधिक डीलरों की संख्या का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया जाना।
- (6) 50,000/- रुपये की न्यूनतम मासिक आय गारंटी या सरकारी कर्मचारियों के लाभ लागू किए जाएं।
- (7) राष्ट्रीय महासचिव ने सदन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री डी.पी. वाधवा द्वारा व्यक्तिगत एफपीएस डीलरों के लाइसेंस तत्काल वापस लेने की विधिवत सिफारिश की याद दिलाई। उसी समय ऐसी व्यक्तिगत डीलर विरोधी सिफारिश का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक वाद (केस) दायर किया और कुछ सुनवाई के बाद माननीय न्यायमूर्तिदलजीत सिंह भंडारी ने वाधवा समितिके निर्णय पर रोक लगाने का आदेश पारित किया।
- (8) माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ हुई बैठक के परिणामों पर बैठक में चर्चा हुई है लेकिन अभी तक न तो कोई कार्रवाई हुई है और न ही कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

उपस्थित सभी लोगों द्वारा रखी गई आम समस्याएं और मांगें तथा अपने विचार इस प्रकार हैं:-

- 1) श्री बरुण कुमार सिंह (राष्ट्रीय सचिव, बिहार) - हम अपने राज्य में डीबीटी को लागू नहीं होने देंगे तथा फेडरेशन द्वारा लिए गए निर्णय का पालन करेंगे तथा उसका समर्थन करेंगे। अनुशासन बनाए रखा जाना चाहिए।



ALL INDIA FAIR PRICE SHOP DEALERS' FEDERATION

Regd. No. District East/Society/273-2011 of Govt. of NCT. of Delhi

Regd. Office : S-562, School Block, 'AKHAND HINDUSTHAN BHAWAN' Shakarpur, Delhi - 110 092, Mobile : 98110 12241/9871421221

Head Office : AC-164, Prafulla Kanan (East), Kestopur, Kolkata - 700 101, West Bengal

Phone : (033) 2591 3871/Mobile : 9875308556 / 98301 35530 / 9748777006, mail : gs@aifpsdf.org/Website : www.aifpsdf.org/WhatsApp : 9875308556 / 9830135530/Facebook : facebook.com@aifpsdf

Prof. Saugata Roy
Hon'ble M.P. Lok Sabha
Chief Advisor
Ph: 2290 3272, 2422 0772
Mob.: 9830031220 / 9013180175

Shri Kacham Krishnamurthy
President
Mobile : 9849024567
8008018012

Shri Biswambhar Basu, B.Com, LLB
General Secretary
Ph. : (033) 2591-3871
Mobile : 98753-08556 / 98301-35530 / 97487-77000
WhatsApp : 98753-08556 / 98301-35530

Shri Dharani Dhar Borah
Treasurer
Mobile : 9678270358

Advisory Committee : Shri Pushparaj (Kaka) Deshmukh, Shri Kiranpal Singh Tyagi, Shri Kalicharan Gupta, Sardar Inderjit Singh

- 2) श्री शिव कुमार गर्ग(राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दिल्ली) - हमें अपने हक के लिए एकजुट होकर लड़ना चाहिए। कोरोना महामारी के दौरान जिन एफपीएस डीलरों ने अपनी सेवाएं दी, उनमें से कई की मृत्यु हो गई, लेकिन किसी भी लाभार्थी/कार्डधारक को बिना भोजन के मरने के लिए नहीं छोड़ा गया। हमें स्थानीय भाषा में पत्र लिखकर अपने सांसदों से सदन में हमारी समस्याओं के बारे में प्रश्न उठाने के लिए कहना चाहिए।
- 3) श्रीमती सरलिंडा खारलुकी (मेघालय) - फेडरेशन के दैनिक कार्योंकी जानकारी न होने के कारण राष्ट्रीय महासचिव के मार्गदर्शन के बावजूद कुछ नहीं कह सकीं।
- 4) श्री अजय गुप्ता (अध्यक्ष, जम्मू-कश्मीर) हम अपने लिए कुशलता से काम नहीं करते, बल्कि सिर्फ फोटो सेशन करते हैं। हमें डीबीटी के क्रियान्वयन के खिलाफ लड़ने के लिए फेडरेशन को मजबूत करना चाहिए। हमें जमीनी स्तर तक सभी डीलरों को डीबीटी के बारे में समझाना चाहिए और इसके खिलाफ लड़ने के लिए उनका समर्थन मांगना चाहिए। अगर सरकार हमारा समर्थन नहीं करती है तो हम उसे बदल सकते हैं।
- 5) श्री जॉनी नेल्लोर (केरल से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष) - पीडीएस में कई तरह की समस्याएं हैं। केरल में 14,300 डीलर हैं। हमें डर है कि डीबीटी लागू हो जाएगा, जिससे हम बेरोजगार हो जाएंगे। माननीय केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया कि डीबीटी तभी लागू होगा, जब राज्य सरकार सिफारिश करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मार्जिन राज्य सरकारों का विषय है। हमने राज्य सरकार से मार्जिन बढ़ाने के लिए कहने का फैसला किया है। मानदेय के रूप में 30,000 रुपये, दुकान का किराया और तीन कर्मचारियों का वेतन। हमने केंद्रीय खाद्य मंत्री और नीतिआयोग को ज्ञापन सौंपा।
- 6) श्री नागेंद्र जेना (ओडिशा से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष) हमारे लिए समस्या है, हमें इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। ओडिशा में बोले। डीबीटी एक बड़ी समस्या है।
- 7) श्री करमजीत सिंह (पंजाब से राष्ट्रीय सहायक सचिव) - पंजाब में डीबीटी लागू नहीं होने दिया जाएगा, डीबीटी के कारण चंडीगढ़ में सभी डीलर समाप्त हो गए।
- 8) श्री डिम्पल कुमार शर्मा(राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राजस्थान) - श्री जॉनी नेल्लोर को बधाई जिन्होंने डीबीटी के सम्बन्ध में खाद्य मंत्री से मुलाकात की। हमें सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर निर्णय का इंतजार करना चाहिए तथा एक ऐतिहासिक रैली का आयोजन करना चाहिए। हमें लाभार्थियों को भी विश्वास में लेना चाहिए तथा उन्हें यह एहसास कराना चाहिए कि हम उनके अधिकारों के लिए भी लड़ रहे हैं। हमें एक बार शुरू किए गए आंदोलन से पीछे नहीं हटना चाहिए तथा तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते।
- 9) श्री राजेश तिवारी (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश) - हम अपने आंदोलन को हमेशा मजबूत करने के लिए संख्याबल देते हैं। डीबीटी को किसी भी कीमत पर बंद किया जाना चाहिए। सभी आंदोलन कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहेगा।
- 10) श्री रेवाधर बृजवासी (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तराखंड) - हम डीबीटी के क्रियान्वयन के खिलाफ लड़ेंगे। पहाड़ी राज्य होने के कारण समस्याएं बहुत हैं।
- 11) श्री धरणीधर बोरा (असम से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष) हमारे देश में 36 राज्य हैं, लेकिन केवल 13 राज्य ही मौजूद हैं। हमें अपनी बेहतरी के लिए एक ही रास्ते पर चलना चाहिए। सभी को एकजुट करने के लिए कौन सी दवाई दी जानी चाहिए, इस पर निर्णय लेना चाहिए।
- 12) श्री सौरभ गुप्ता (दिल्ली मीडिया प्रभारी) डीबीटी को लागू नहीं होने दिया जाना चाहिए।
- 13) श्री गुरुदेव पासवान (बिहार से एक अन्य मीडिया प्रभारी) - वर्तमान समय में डीबीटी हमारी मुख्य समस्या है और इसे रोका जाना चाहिए।
- 14) श्री राज कुमार मित्तल (पश्चिम बंगाल से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष) हमें न्याय चाहिए लेकिन किससे? जब हम केंद्र सरकार से न्याय की मांग करते हैं तो वह राज्य सरकार पर आरोप मढ़ देती है और राज्य सरकार वादा तो करती है लेकिन



ALL INDIA FAIR PRICE SHOP DEALERS' FEDERATION

Regd. No. District East/Society/273-2011 of Govt. of NCT. of Delhi

Regd. Office : S-562, School Block, 'AKHAND HINDUSTHAN BHAWAN' Shakarpur, Delhi - 110 092, Mobile : 98110 12241/9871421221

Head Office : AC-164, Prafulla Kanan (East), Kestopur, Kolkata - 700 101, West Bengal

Phone : (033) 2591 3871 Mobile : 9875308556 / 98301 35530 / 9748777006, mail : gs@aifpsdf.org Website : www.aifpsdf.org WhatsApp : 9875308556 / 9830135530 Facebook : facebook.com@aifpsdf

Prof. Saugata Roy
Hon'ble M.P. Lok Sabha
Chief Advisor
Ph.: 2290 3272, 2422 0772
Mob.: 9830031220 / 9013180175

Shri Kacham Krishnamurthy
President
Mobile : 9849024567
8008018012

Shri Biswambhar Basu, B.Com, LLB
General Secretary
Ph. : (033) 2591-3871
Mobile : 98753-08556 / 98301-35530 / 97487-77000
WhatsApp : 98753-08556 / 98301-35530

Shri Dharani Dhar Borah
Treasurer
Mobile : 9678270358

Advisory Committee : Shri Pushparaj (Kaka) Deshmukh, Shri Kiranpal Singh Tyagi, Shri Kalicharan Gupta, Sardar Inderjit Singh

कुछ नहीं करती। हम यहां पीडीएस के कुछ बहुत ही प्रतिष्ठित नेताओं द्वारा हमारी समस्याओं के बारे में एक प्रभावशाली चर्चाके लिए एकत्र हुए हैं लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि कोई भी किसी पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका। यह सच है कि हमें अपने अधिकार के लिए हर स्तर पर लड़ना होगा।

15) श्री गिरीश तिवारी (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उ.प्र.) - घोषित किया कि हमारा आन्दोलन कार्यक्रम हमारे तय कार्यक्रम के अनुसार सभी राज्यों में आयोजित किया जाना चाहिए तथा उ.प्र. पूरी ताकत से प्रयास करेगा।

श्री आँकार नाथ झा (झारखंड), राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष - सबसे दुखद समय, राहु, केतु और शनितीनों ग्रहों ने हमारे पीडीएस को निगल लिया है। उन्होंने पूछा कि अगर केरल में डीबीटी लागू नहीं हो रहा है, तो अन्य राज्यों में क्यों। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल आदिमें चुनाव होने वाले हैं। पीडीएस डीलरों को संघर्षकरना चाहिए और अपनी मांगें सामने रखनी चाहिए, जून से पहले अनुकंपा + मानदेय। डीआरसी की ज़ेरॉक्स कॉपी + एक वास्तविक लाभार्थीका आधार कार्ड, डीबीटी प्रस्ताव लागू न होने की गारंटी - 50,000/- रुपये प्रतिमाह आय की गारंटी या केंद्र सरकार के कर्मचारी लाभ।

अपने-अपने राज्यों के नेताओं द्वारा बैठक के अध्यक्ष से अनुरोध करने पर निम्नलिखित सदस्यों को बोलने की अनुमति दी गई:-

(1) Shri Sachchidanand (Bihar), (2) Shri Aman Kumar (J&K), (3) Shri Madan Lal Gujjar (Rajasthan), (4) Shri Deep Narayan (U.P.) and (5) Shri Raghuvanshi Sharma (Bihar).

श्री मदन लाल गुज्जर जी से अनुरोध किया गया कि वे यथाशीघ्र माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से मुलाकात का समय प्राप्त करें।

बैठक के अंत में महासचिव ने उपस्थित सदस्यों के समक्ष अपनी कुछ टिप्पणियां और सुझाव रखे:

* एफपीएस डीलरों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रूप में मानने और डीलरों के लिए वेतन प्रणाली शुरू करने की हमारी महत्वपूर्ण मांग को स्थापित करना। इस संबंध में, हमें आंतरिक रूप से सर्वेक्षण करना चाहिए कि कितने डीलर 60 वर्षकी आयु पार कर चुके हैं। 60 वर्षसे अधिक आयु के डीलरों की कुल संख्या (31 मार्च 2025 तक) दर्शाते हुए जिलावार डेटा हमारे मुख्य कार्यालय को भेजा जा सकता है।

* एनएफएसए के तहत केंद्र सरकार 81 करोड़ 35 लाख गरीब लोगों को राशन उपलब्ध करा रही है, लेकिन केवल 80 करोड़ 52 लाख लोगों को ही राशन मिल रहा है, यानी 79 लाख गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है।

* झारखंड के खूंटी में स्मार्टपीडीएस की पायलट परियोजना शुरू होने से केंद्र सरकार को वितरण का वास्तविक समय पर हिसाब मिल सकेगा।

* हाल ही में सांसदों के वेतन में 24,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई, लेकिन एनएफएसए के तहत हर तीन साल में मार्जिन बढ़ाने के प्रावधान के बावजूद राशन डीलरों को उचित मार्जिन के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है।

* एनएफएसए के तहत भारत सरकार 19 करोड़ 53 लाख 78 हजार 4 सौ 58 परिवारों को राशन उपलब्ध करा रही है, जिसमें 4 करोड़ 7 लाख 32 हजार 6 सौ 62 परिवारों के राशन कार्ड बैंक खातों से जोड़े जा चुके हैं।

* पिछले 10 वर्षों में नरेन्द्र मोदी सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपये के कर्जमाफ किये हैं, जिनमें से 9 लाख करोड़ रुपये अमीर व्यापारियों के थे।

* 2011 के बाद जनगणना न होने के कारण 14 करोड़ गरीब लोग राशन से वंचित रह रहे हैं।

* मूल्य वृद्धिसे लड़ने और राशन डीलरों की व्यवहार्यता को कुछ हद तक बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने फेड के माध्यम से राशन डीलरों को "भारत" ब्रांड चावल और दालें उपलब्ध करा रही है, लेकिन नौकरशाही इस योजना को सफल नहीं होने दे रही है।

* अमृत भारत, सबका साथ सबका विकास का नारा केवल मध्यम वर्गको गुमराह कर रहा है, मध्यम वर्गकी आय बढ़ाने की बजाय आय और व्यय का अनुपात वर्ष 1820 के बराबर है।



ALL INDIA FAIR PRICE SHOP DEALERS' FEDERATION

Regd. No. District East/Society/273-2011 of Govt. of NCT. of Delhi

Regd. Office : S-562, School Block, 'AKHAND HINDUSTHAN BHAWAN' Shakarpur, Delhi - 110 092, Mobile : 98110 12241/9871421221

Head Office : AC-164, Prafulla Kanan (East), Kestopur, Kolkata - 700 101, West Bengal

Phone : (033) 2591 3871 Mobile : 9875308556 / 98301 35530 / 9748777006, mail : gs@aifpsdf.org Website : www.aifpsdf.org WhatsApp : 9875308556 / 9830135530 Facebook : facebook.com@aifpsdf

Prof. Saugata Roy
Hon'ble M.P. Lok Sabha
Chief Advisor
Ph. : 2290 3272, 2422 0772
Mob. : 9830031220 / 9013180175

Shri Kacham Krishnamurthy
President
Mobile : 9849024567
8008018012

Shri Biswambhar Basu, B.Com, LLB
General Secretary
Ph. : (033) 2591-3871
Mobile : 98753-08556 / 98301-35530 / 97487-77000
WhatsApp : 98753-08556 / 98301-35530

Shri Dharani Dhar Borah
Treasurer
Mobile : 9678270358

Advisory Committee : Shri Pushparaj (Kaka) Deshmukh, Shri Kiranpal Singh Tyagi, Shri Kalicharan Gupta, Sardar Inderjit Singh

* यह अच्छी तरह जानते हुए किछोटे तारे सूर्यके साथ नहीं रह सकते, हमने अपने चल रहे आंदोलन में सभी राज्य-वार भाई संगठनों को शामिल करने का फैसला किया है। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता किहमारा फेडरेशन पीडीएस में एक किंवदंती है। यह हमारे लिए शर्मकी बात है किइस अभूतपूर्वस्थितिमें भी सभी एफपीएस डीलरों ने अपने भरण-पोषण के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को एकजुट नहीं किया है।

* नीतिआयोग ने लाभार्थियों से 1 रुपये से 1.50 रुपये प्रतिकिलोग्राम की दर से मूल्य वसूलने का सुझाव दिया।

* प्रत्येक माह की 1-10 तारीख तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों का वितरण तथा 11 से 30 तारीख तक अन्य सरकारी योजनाओं के तहत वितरण।

* चीनी, खाद्य तेल और दालें जैसी अन्य वस्तुएं सब्सिडी दरों पर।

न्यायालयीन मामले के लिए एक उप-समितिगठित की गई:-

- (1) अध्यक्ष- राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के. कृष्णमूर्तिजी,
 - (2) संयोजक - राष्ट्रीय महासचिव, श्री विश्वम्भर बासु
 - (3) Cashier - National Treasurer, Shri Dharani Dhar Borah,
- सदस्य - सभी राज्यों के अध्यक्ष एवं सचिव।

* स्मार्टपीडीएस के लिए तमिलनाडु को छोड़कर 35 राज्यों के बीच समझौता जापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।

* स्मार्टपीडीएस के तत्काल क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने राज्य परामर्श एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं तथा विभिन्न राज्यों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है, जिसमें यह स्पष्ट हुआ है किहमारी बैठक के दिन/तारीख को भारत सरकार ने दिल्ली में डीबीटी के क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण दिया है, लेकिन यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी पदाधिकारी ने सदन को इस ज्वलंत मुद्दे के बारे में सूचित नहीं किया।

* 12 मार्चको लोक सभा में माननीय केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने तारांकित प्रश्नों के उत्तर में इस मुद्दे को संसद के समक्ष उठाया।

* पूरे भारत में पीडीएस लाभार्थियों का ई-केवाईसी लगभग 75.69% पूरा हो चुका है।

* इसके अलावा, 2013 से 2025 तक (आज तक) हटाए गए राशन कार्डोंको दर्शाने वाले राज्यवार विस्तृत विवरण पर भी चर्चाकी गई। सदन ने यह सवाल उठाया किराज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों ने उन खाद्य अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है जिन्होंने 5,87,22,894 राशन कार्डजारी किए हैं।

संगठनात्मक चर्चाएँ:-

1) कर्नाटक राज्य के नेताओं से अनुरोध किया गया कि वे सभी बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित रहें। अपने राज्य में किसी भी आपात स्थितिमें कम से कम 1(एक) सदस्य को प्रतिनिधित्व के लिए भेजा जाना चाहिए या भाग लेना चाहिए।

2) हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रहलाद भाई मोदी की अस्वस्थता के कारण उनसे अनुरोध किया गया है कि वे नियमित रूप से गुजरात से किसी अन्य नेता की उपस्थितिपर विचार करें।

3) जनाब रमजान अली अंसारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी अपनी वृद्धावस्था के कारण सभी कार्यक्रमों में भाग लेने में असमर्थ हैं। उन्हें फेडरेशन के सलाहकार के रूप में सम्मानित किया जा सकता है।

4) वर्चुअल बैठकों में भागीदारी और भौतिक बैठकों में उपस्थितिबहुत अनियमित हो गई है, जो महाराष्ट्र जैसे राज्य के लिए बिल्कुल भी वांछनीय नहीं है।

5) तेलंगाना के अध्यक्ष श्री नई कोटिराजू और संगठन सचिव श्री ज्योतिधर सिंह (सोनू) तथा आंध्र प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़के सभी नेतागण बहुत अनियमित हैं, उनसे अनुरोध किया गया कि वे फेडरेशन को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से आगे आएँ।



ALL INDIA FAIR PRICE SHOP DEALERS' FEDERATION

Regd. No. District East/Society/273-2011 of Govt. of NCT. of Delhi

Regd. Office : S-562, School Block, 'AKHAND HINDUSTHAN BHAWAN' Shakarpur, Delhi - 110 092, Mobile : 98110 12241/9871421221

Head Office : AC-164, Prafulla Kanan (East), Kestopur, Kolkata - 700 101, West Bengal

Phone : (033) 2591 387 Mobile : 9875308556 / 98301 35530 / 9748777000, mail : gs@aifpsdf.org Website : www.aifpsdf.org WhatsApp : 9875308556 / 9830135530 Facebook : facebook.com@aifpsdf

Prof. Saugata Roy
Hon'ble M.P. Lok Sabha
Chief Advisor
Ph.: 2290 3272, 2422 0772
Mob.: 9830031220 / 9013180175

Shri Kacham Krishnamurthy
President
Mobile : 9849024567
8008018012

Shri Biswambhar Basu, B.Com, LLB
General Secretary
Ph. : (033) 2591-3871
Mobile : 98753-08556 / 98301-35530 / 97487-77000
WhatsApp : 98753-08556 / 98301-35530

Shri Dharani Dhar Borah
Treasurer
Mobile : 9678270358

Advisory Committee : Shri Pushparaj (Kaka) Deshmukh, Shri Kiranpal Singh Tyagi, Shri Kalicharan Gupta, Sardar Inderjit Singh

(क) असम से उपाध्यक्ष पद पर श्री देबेन चौधरी बोरो के स्थान पर श्री सुकुमार वायरी को नियुक्त किया गया है।

(ख) श्री अजय कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, जम्मू-कश्मीर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है।

आंदोलन के लिए

हमारे आंदोलन के दौरान ड्रेस कोड रखा जाएगा, टी-शर्ट और कैप दिल्ली से उचित दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस संदर्भ में, हर नेता संपर्क कर सकता है:-

फैबकलूज़, नई दिल्ली के श्री राजीव,

मोबाइल 94347 43990

जो अपनी बारी में सीधे आपके गंतव्य तक सामान पहुंचाएंगे

इसलिए, सभी लीडर और डीलरों से अनुरोध है कि वे श्री राजीव से संपर्क करें और तदनुसार उन्हें ऑर्डर दें तथा सीधे भुगतान करें।

अंत में सभी को धन्यवाद दिया गया तथा राष्ट्रगान के साथ बैठक को अगली बैठक तक के लिए समाप्त घोषित कर दिया गया।

ओंकार नाथ झा
बैठक के अध्यक्ष एवं
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष
28/03/2025

राज कुमार मित्तल
बैठक के समन्वयक
एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

बिश्वम्भर बासु
राष्ट्रीय महासचिव
मोबाइल: (+91) 9875308556